भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 445
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य
445. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं मिल रहा है और उन्हें अपनी फ़सल दिल्ली के बाहर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) एमएसपी लागू न होने से दिल्ली में कितने किसान प्रभावित हुए हैं और कुल कितनी फ़सलें दिल्ली के बाहर बेची गई हैं; और
(ग) दिल्ली में किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस योजना को लागू करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार प्रतिवर्ष, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, दिल्ली सहित पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। सरकार की मूल्य नीति, किसानों की उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदकर उन्हें लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तथापि, किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए सुविधाजनक हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) जो कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का एक घटक है, जिसमें निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों के अनुरूप पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से अधिसूचित तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है, जब फसलोपरांत कीमतें एमएसपी से नीचे आ जाती हैं। यह योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो खरीदी गई वस्तुओं को मंडी कर लगाने से छूट देने और योजना के दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक बोरों, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी, पीएसएस संचालन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण आदि सहित रसद व्यवस्था में केंद्रीय नोडल एजेंसियों की सहायता करने के लिए सहमत होती है। तथापि, पीएसएस के तहत दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****